(b) the details of measures taken by the Government to prevent the felling of trees and to control and prevent fires in forests; and

(c) the details of financial assistance given to Uttar Pradesh during the last three years for the development of forests?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) An area of 39,281.73 hectares is reported to have been burnt by fire in Uttar Pradesh during the last three years. Information with regard to loss of forest due to felling of trees is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) Guidelines have been issued to the State Governments from time to time for protection of forests against felling of trees. Some of these guidelines are as follows:—

(i) To avoid felling of natural forests and where such felling are inevitable for restoration of crop or other silvicultural considerations, it should be restricted to areas not exceeding 10 hectares in the hills and 25 hectares in the plains.

(ii) To consider banning of fellings in the hills above 1,000 metres, at least for some years.

(iii) To identify critical areas in the hills and mountains which require protection from felling of forests and need immediate vigorous afforestation.

(iv) To set apart 4 per cent of the geographical areas as protection area like wildlife sanctuaries, national parks biosphere reserves etc.

Measures taken by the Government to control and prevent fires in forests include clearance and maintenance of fire lines, controlled burning along roads and paths, seeking cooperation of the people through publicity and extinguishing forests fires with the help of counter fires and implements including hand tools.

(c) An amount of Rs. 8755.00 lakhs has been given to Uttar Pradesh as Central assistance for afforestation schemes during the last 3 years.

Extension of Term of the Chairman, Bank of Baroda

2427. SHRI RAOOF VALIULLAH:
SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to extend the term of office of the Chairman of Bank of Baroda, if so, for how many years;

(b) whether it is a practice not to extend the term of any executive beyond 60 years, if so, what were the compelling reasons for this extension; and

(c) whether Government have received reports of the Central Vigilance Commission and Reserve Bank of India against the present Chairman, if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) and (cb) After taking all relevant factors into consideration, Shri Premjit Singh has been reappointed for a further period of one year as the Chairman and Managing Director of Bank of Baroda.

(c) The Chairman and Managing Director of Bank of Baroda does not figure in the records of Central Vigilance Commission, Reserve Bank's investigations into the complaints against the present Chairman of Bank of Baroda reveal that they were of too general a nature and not borne out by facts.

भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की धीमी गति

@2428. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशिया

के लिए विश्व बैंक के उप-प्रधान श्री अरिलो करावाँसो कानोगुलू के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि भारत में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 16 परियोजनाओं की गति बहुत धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं और उस पर धीमी गति से कार्य होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में इन्हें शीघ्र ही पूरा करने के लिए क्या-क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) जी, हां। जिस विवरण का हवाला दिया गया है, वह संबंधित क्षेत्रों में अन्य परियोजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत धीमे संवितरण वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिये किये गये एक पुनरीक्षण के निष्कर्ष पर आधारित है। पता लगाई गई ऐसी सोलह परियोजनाओं की सूची निम्नलिखित है :

1. केन्द्रीय विद्युत पारेषण
2. इंदिरा सरोवर
3. फरक्का तापीय विद्युत–II
4. केरल विद्युत
5. ऊपरी इंद्रावती विद्युत
6. पश्चिमी बंगाल लघु सिंचाई
7. ऊपरी गंगा सिंचाई
8. महाराष्ट्र सिंचाई
9. वर्षा पोषित जल-विभाजक
10. हिमालयाई जल-विभाजक
11. राष्ट्रीय कृषि विस्तार–I
12. तमिलनाडु जल आपूर्ति
13. मध्य प्रदेश शहरी
14. कलकत्ता शहरी–III
15. रेलवे विद्युतीकरण
16. झरिया कोकिंग कोयला

अपेक्षाकृत धीमे संवितरण निष्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य घटकों में से कुछ हैं : भूमि अधिग्रहण और अधिदेशात्मक स्वीकृति प्राप्त करने में विलम्ब, जिनमें पर्यावरणिक और वानिकी संबंधी स्वीकृति भी सम्मिलित है, तकनीकी समस्याएं अप्रत्याशित लागत बचतें तथा राज्यक्षेत्र की परियोजनाओं में दूसरे पक्ष द्वारा अपर्याप्त निधिकरण।

परियोजनाओं के यथासमय क्रियान्वित हो जाने को सुगम बनाने के लिए गहन पुनरीक्षण के माध्यम से एक विस्तृत अनुश्रवण प्रणाली तैयार की गई है जिसमें आर्थिक कार्य विभाग, प्रशासनिक मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार शामिल है। इसके अतिरिक्त, इसी उद्देश्य से राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विदेशी सहायता से चल रही परियोजनाओं के बारे में तत्परतापूर्वक त्रैमासिक पुनरीक्षणों की व्यवस्था करें।

शहर के गरीब लोगों को ऋण दिया जाना

2429. श्री अजीत जोगी :
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहर के गरीब लोगों की स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिये गए ऋणों के उपयोग अथवा दुरुपयोग की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बहुत बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को ऋण दिये गये हैं तथा इसलिये उन्होंने उनका उपयोग उस हेतु नहीं किया है जिस हेतु ये ऋण मंजूर किये गये थे ;

(घ) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई भूमिका जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को देने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का इशारा शहरी गरीबों के स्व-रोजगार कार्यक्रम की ओर है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी गरीबों को जिन बैंक-शाखाओं द्वारा